



BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानों का आकलन

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

02 सितंबर, 2026

सामयिक जीडीपी श्रृंखला

31 अगस्त 2026 को 2022-23 को आधार वर्ष मानकर वार्षिक और तिमाही जीडीपी अनुमानों की सामयिक श्रृंखला जारी की गई। इस नई श्रृंखला में 2022-23 को आधार मानकर तैयार किए गए नए 'आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक' और 'बैंकिंग सेवा मूल्य सूचकांक' के साथ-साथ अद्यतन प्रशासनिक आंकड़ों को भी शामिल किया गया है।

जीडीपी की नई श्रृंखला में दो प्रमुख बदलाव महत्वपूर्ण हैं: आधार वर्ष में परिवर्तन और विनिर्माण क्षेत्र के लिए 'दोहरी अपस्फीति' पद्धति को अपनाया जाना।

- राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में आधार वर्ष उन संदर्भ कीमतों को निर्धारित करता है, जिनका उपयोग वास्तविक विकास दर की गणना के लिए किया जाता है। इसमें समय-समय पर बदलाव किए जाते हैं,

अपस्फीति, मौजूदा कीमतों (नाममात्र मूल्य) से दो समय-अवधियों के बीच कीमतों में बदलाव के प्रभाव को हटाकर, स्थिर कीमतों पर वास्तविक मूल्य (वास्तविक मूल्य) निर्धारित करने की प्रक्रिया है।

- ताकि अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलावों को शामिल किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि सापेक्ष कीमतें मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को सही ढंग से दर्शाती रहें।
- अद्यतन की गई जीडीपी श्रृंखला बेहतर और अधिक मजबूत कार्यप्रणाली को दर्शाती है। विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों के लिए 'दोहरा अपस्फीति' पद्धति अपनाई गई है। इसके तहत, स्थिर कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) की गणना करने के लिए उत्पादन और मध्यवर्ती खपत को अलग-अलग अपस्फीति समायोजन के साथ मापा जाता है।

आईएमएफ सकल घरेलू उत्पाद की मात्रा-आधारित गणना के लिए 'दोहरा अपस्फीति' पद्धति को पसंदीदा तरीका मानता है।

2026-27 की पहली तिमाही में भारत के जीडीपी प्रदर्शन के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें: [भारत का जीडीपी प्रदर्शन](#)

भारत के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में किए गए संशोधनों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें: [महत्वपूर्ण तथ्यों की गणना: भारत के राष्ट्रीय लेखा और मुख्य आर्थिक सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाना](#)

अपस्फीति कार्यप्रणाली

- 2026-27 की पहली तिमाही में, विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन और आगत की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद, विनिर्माण क्षेत्र के जीवीए के निहित अपस्फीतिकारक में -1.5% की नकारात्मक मुद्रास्फीति दर कैसे दर्ज हो

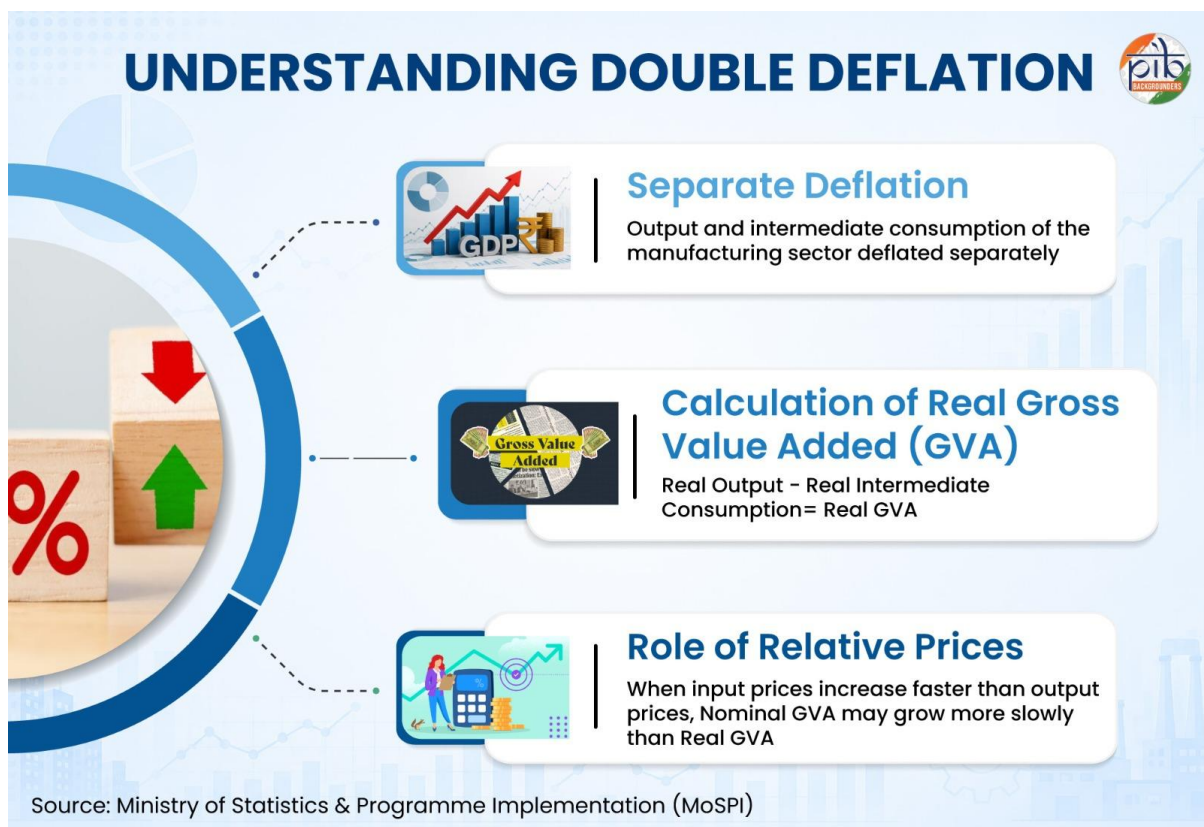
सकती है, जबकि कृषि क्षेत्र में 3.9% की सकारात्मक मुद्रास्फीति दर दर्ज की गई?

दोहरी अपस्फीति को समझना: दोहरी अपस्फीति पद्धति में विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन और मध्यवर्ती खपत को अलग-अलग अपस्फीति समायोजन के माध्यम से मापा जाता है। वास्तविक जीवीए, वास्तविक उत्पादन में से वास्तविक मध्यवर्ती खपत घटाकर निकाला जाता है। इसलिए, जब इनपुट की कीमतें आउटपुट की कीमतों की तुलना में तेजी से बढ़ती हैं, तो कीमतों में सापेक्ष बदलाव के कारण नॉमिनल जीवीए की वृद्धि दर वास्तविक जीवीए की तुलना में धीमी हो सकती है।

नतीजतन, निहित जीवीए अपस्फीतिकारक, जो नाममात्र और वास्तविक जीवीए की तुलना से निर्धारित होता है, नकारात्मक मुद्रास्फीति दर दिखा सकता है, भले ही उत्पादन व आगत दोनों की कीमतों में वृद्धि हो रही हो।

महत्वपूर्ण बात यह है कि नकारात्मक जीवीए अपस्फीतिकारक का अर्थ अपने आप कम वास्तविक वृद्धि नहीं होता। वास्तविक जीवीए की वृद्धि वास्तविक उत्पादन और वास्तविक मध्यवर्ती खपत में होने वाले सापेक्ष बदलाव पर निर्भर करती है।

विनिर्माण क्षेत्र में निहित अपस्फीतिकारक में नकारात्मक मुद्रास्फीति का मतलब यह नहीं है कि विनिर्माण की कीमतें गिर गई हैं। उत्पादन और आगत के मूल्य अपस्फीतिकारक तथा निहित सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) अपस्फीतिकारक के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है।



उपर बताई गई स्थिति को समझने के लिए नीचे एक उदाहरण दिया गया है:

	वर्ष 1	वर्ष 2	विकास दर
उत्पादन का सकल मूल्य	1,000 करोड़	1,200 करोड़	20.0%
मध्यवर्ती उपभोग	800 करोड़	976 करोड़	22.0%
नॉमिनल सकल मूल्य वर्धन (वर्तमान)	200 करोड़	224 करोड़	12.0%
पीपीआई उत्पादन सूचकांक	100	110	10.0%
पीपीआई आगत सूचकांक	100	114	14.0%
घटा हुआ उत्पादन(स्थिर)	1,000 करोड़	1,091 करोड़	9.1%
अपस्फीत आगत (स्थिर)	800 करोड़	856 करोड़	7.0%
वास्तविक मूल्य वर्धन (स्थिर)	200 करोड़	235 करोड़	17.5%

मौजूदा कीमत वृद्धि दर (%)	12.0%
स्थिर मूल्य वृद्धि दर (%)	17.5%

उदाहरण के अनुसार, नॉमिनल जीवीए में 12% की वृद्धि होती है, जबकि वास्तविक जीवीए में 17.5% की वृद्धि होती है। इसके परिणामस्वरूप नकारात्मक निहित जीवीए अपस्फीतिकारक प्राप्त होता है। यह दोहरे अपस्फीति के तहत उत्पादन और आगत की कीमतों में होने वाले सापेक्ष बदलाव को दर्शाता है।

2026-27 की पहली तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र का जीवीए 'दोहरा अपस्फीति' पद्धति से तैयार किया गया, जिसमें उत्पादन और मध्यवर्ती खपत को अलग-अलग अपस्फीति समायोजन के साथ मापा गया। इस दौरान, उत्पादन की कीमतों की तुलना में आगत की कीमतों में अधिक तेजी से वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र में नॉमिनल जीवीए की वृद्धि 7.7% रही, जबकि वास्तविक जीवीए की वृद्धि 9.2% रही। नाममात्र और वास्तविक जीवीए की वृद्धि दर के बीच इस अंतर के कारण -1.5% का नकारात्मक निहित जीवीए अपस्फीतिकारक दर्ज हुआ।

उदाहरण के लिए, ऐसी कुछ गतिविधियां जिनमें उत्पादन की कीमतों की तुलना में आगत की कीमतों में अधिक वृद्धि देखी गई, उनमें वस्त्र एवं कपास ओटाई, मूल धातुओं का निर्माण तथा रबर और प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण शामिल हैं।

ओईसीडी के शोध पत्रों में बताया गया है कि दोहरी अपस्फीति पद्धति अपनाने वाले देशों में वैश्विक ऊर्जा और कच्चे माल के संकट के दौरान विनिर्माण क्षेत्र के निहित अपस्फीतिकारक में अस्थिरता या नकारात्मक दरें देखने को मिल सकती हैं। आयातित कच्चे माल पर अधिक निर्भर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में उतार-चढ़ाव के दौरान विनिर्माण क्षेत्र के अपस्फीतिकारक का नकारात्मक होना एक सामान्य स्थिति हो सकती है।

तिमाही स्तर पर, कृषि जीवीए को सबसे पहले उत्पादन के अनुमानों के आधार पर स्थिर कीमतों पर तैयार किया जाता है। इसके बाद, संबंधित उत्पादक मूल्य सूचकांक का उपयोग करके स्थिर कीमतों पर तैयार अनुमानों को समायोजित किया जाता है, जिससे कृषि जीवीए के मौजूदा कीमतों पर अनुमान प्राप्त होते हैं।

2026-27 की पहली तिमाही में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन समूह के उत्पादन उत्पादक मूल्य सूचकांक में लगभग 5% की वृद्धि हुई। चूंकि उत्पादन की कीमतों में वृद्धि हुई और कृषि कानॉमिनल जीवीए काफी हद तक इन्हीं उत्पादन कीमतों पर निर्भर करता है, इसलिए इसकी निहित मुद्रास्फीति दर 3.9% पर सकारात्मक रही।

2. 'दोहरी अपस्फीति' की पद्धति 'निजी अंतिम उपभोग व्यय' (पीएफसीई) पर कैसे लागू होती है, और क्या यह सीधे पीएफसीई की गणना में शामिल होती है?

दोहरी अपस्फीति की पद्धति सीधे तौर पर पीएफसीई की गणना में शामिल नहीं होती है।

दोहरी अपस्फीति उत्पादन-पक्ष की एक तकनीक है, जिसका उपयोग किसी उद्योग के जीवीए का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। इसमें स्थिर कीमतों पर सकल उत्पादन और मध्यवर्ती खपत को अलग-अलग अपस्फीति समायोजन के साथ मापा जाता है। चूंकि पीएफसीई अंतिम मांग, यानी अंतिम उपयोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए खर्च का माप है, इसलिए इसमें घटाने के लिए कोई मध्यवर्ती खपत नहीं होती है।

तिमाही स्तर पर, पीएफसीई का अनुमान विस्तृत वस्तु या वस्तु-समूह के स्तर पर लगाया जाता है। खाद्य पदार्थों और विनिर्मित उत्पादों जैसी विभिन्न वस्तुओं के लिए पहले उपयुक्त मात्रा सूचकों का उपयोग करके स्थिर कीमतों पर अनुमान

तैयार किए जाते हैं। इसके बाद, संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करके मौजूदा कीमतों पर अनुमान निकाले जाते हैं।

पीएफसीई के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रेस्तरां तथा आवास जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए संबंधित उत्पादन सूचकों का उपयोग करके पहले मौजूदा कीमतों पर अनुमान तैयार किए जाते हैं। इसके बाद, उपयुक्त मूल्य सूचकांक का उपयोग करके उनसे संबंधित स्थिर कीमतों पर अनुमान निकाले जाते हैं।

इस प्रकार, 'दोहरी अपस्फीति' पद्धति उत्पादन-पक्ष के जीवीए के अनुमान के लिए प्रासंगिक है और पीएफसीई के अनुमान में इसका सीधे तौर पर उपयोग नहीं किया जाता है।

नाममात्र और वास्तविक अनुमानों को समझना

1. हम 2.5% की अनुमानित जीडीपी महंगाई दर का तालमेल कैसे बिठाएं, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर 3.9% थी और थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित महंगाई दर 9% से अधिक थी?

कीमतों में इस अंतर को यह समझकर स्पष्ट किया जा सकता है कि जीडीपी डिफ्लेटर 'शुद्ध मूल्य वर्धन' की एक अनुमानित कीमत है, न कि लेन-देन की कीमतों का सीधा माप। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) और थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) अर्थव्यवस्था के अलग-अलग पहलुओं को मापते हैं। इनका दायरा और भारांक भी अलग-अलग होते हैं।

इन आर्थिक संकेतकों को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी उनके अलग-अलग उद्देश्यों के अनुसार निर्धारित की जाती है:

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई): यह अंतिम उपभोक्ता के स्तर पर घरेलू उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी की कीमतों में होने वाले बदलाव को दर्शाता है।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई): यह थोक स्तर पर वस्तुओं, कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को दर्शाता है। इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है।

निहित जीडीपी डिफ्लेटर: यह मौजूदा कीमतों पर जीडीपी और स्थिर कीमतों पर जीडीपी का अनुपात होता है। इसमें **पूरी अर्थव्यवस्था** शामिल होती है, जैसे सरकारी खर्च, कॉर्पोरेट निवेश, निर्यात तथा वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सेवाएं, जिनमें बैंकिंग, आईटी और रियल एस्टेट शामिल हैं। चूंकि कच्चे माल की कीमतों में काफी वृद्धि हुई थी, जबकि सेवा क्षेत्र में महंगाई अपेक्षाकृत कम थी, इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर ने उपभोक्ता और थोक वस्तु क्षेत्रों में दिखाई देने वाली ऊंची महंगाई के प्रभाव को कम कर दिया।

Understanding Different Price Measures			
Category	CPI	WPI	Implicit GDP Deflator
Coverage	Household consumption basket of goods and services	Bulk commodities, raw materials and manufactured goods excluding services	Entire economy; government spending, corporate investments, exports, and financial and non-financial services
Measurement Basis	Price changes at the final consumer's end	Price changes at the wholesale level	Derived from current-price and constant-price GDP

Source: Ministry of Statistics & Programme Implementation (MoSPI)

यह जरूरी नहीं है कि निहित जीडीपी डिफ्लेटर, सीपीआई या डब्ल्यूपीआई के साथ-साथ चले। कवरेज, भारांक, मूल्य से जुड़े मानदंड और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन में अंतर के कारण जीडीपी डिफ्लेटर, उपभोक्ता या थोक महंगाई दर से काफी अलग हो सकता है।

नोट: किसी विशेष वस्तु या वस्तु-समूह का अपस्फीति समायोजन, उस वस्तु अथवा समूह के लिए संबंधित मूल्य सूचकांक का उपयोग करके किया जाता है। निहित जीडीपी डिफ्लेटर एक व्युत्पन्न संख्या है, जो वस्तु या वस्तु-समूह के स्तर पर उपयोग किए गए 300 से अधिक अलग-अलग मूल्य अपस्फीतिकारकों के कीमतों पर पड़ने वाले सामूहिक प्रभाव को दर्शाता है।

2. खनन क्षेत्र के नॉमिनल जीवीए और वास्तविक जीवीए के अनुमानों में इतना बड़ा अंतर क्यों है?

तिमाही जीडीपी की गणना में खनन और उत्खनन क्षेत्र के लिए स्थिर कीमतों पर अनुमान तैयार करने हेतु मात्रा सूचक के रूप में संबंधित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का उपयोग किया जाता है। 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान खनन और उत्खनन क्षेत्र की आईआईपी वृद्धि अप्रैल में -3.8%, मई में -1.4% और जून में 1.6% रही।

तालिका-1: आईआईपी में वृद्धि दर			
विवरण	अप्रैल-26	मई-26	जून -26
खनन और पत्थर निकालना	-3.8	-1.4	1.6
(ए) ईंधन खनिज	-5.6	-6.1	-1.8
(बी) धात्विक खनिज, जिनमें दुर्लभ मृदा खनिज भी शामिल हैं	12.4	18.3	39.4
(सी) गैर-धात्विक खनिज, जिनमें गौण खनिज भी शामिल हैं	-10.3	-6.1	-11.7

यह 2026-27 की पहली तिमाही के दौरान खनन और उत्खनन क्षेत्र के वास्तविक जीवीए में -2.4% की वृद्धि के लगभग अनुरूप है।

विभिन्न खनिज समूहों के संबंधित वास्तविक अनुमानों पर उपयुक्त उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) लागू करके नाममात्र के अनुमान निकाले जाते हैं।

2026-27 की पहली तिमाही के पीपीआई आंकड़ों से पता चलता है कि खनन और उत्खनन क्षेत्र में कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। विशेष रूप से, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में अप्रैल में 69.5%, मई में 72.2% और जून में 33.7% की वृद्धि हुई। वहीं, धातु अयस्कों के खनन में क्रमशः 27.6%, 25.2% और 23.5% की महंगाई दर्ज की गई।

तालिका-2: पीपीआई पर आधारित महंगाई दर			
वस्तु का नाम	अप्रैल -26	मई -26	जून -26
खनन और पत्थर निकालना	22.0	21.2	15.5
(ए) धातु अयस्कों का खनन	27.6	25.2	23.5
(बी) कोयला और लिग्नाइट का खनन	-1.6	-2.3	-1.6
(सी) अन्य खनन और उत्खनन	6.9	6.5	8.7
(डी) कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण	69.5	72.2	33.7

इसके अनुसार, 2026-27 की पहली तिमाही में खनन और उत्खनन क्षेत्र की नॉमिनल जीवीए वृद्धि दर 22.3% रही।

वास्तविक और नॉमिनल जीवीए वृद्धि के बीच का बड़ा अंतर, वास्तविक एवं नाममात्र अनुमानों के बीच किसी विसंगति को नहीं दर्शाता है। यह मुख्य रूप से खनिजों की कीमतों, विशेषकर कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और धातु अयस्कों की कीमतों में हुई भारी वृद्धि का परिणाम है।

संशोधन और सांख्यिकीय मिलान

1. मौजूदा वर्ष की जीडीपी को बेहतर दिखाने के लिए पिछले वर्ष की मौजूदा कीमतों पर जीडीपी को 86 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 80 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। यदि पिछले वर्ष के आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं किया गया होता, तो मौजूदा कीमतों पर जीडीपी वृद्धि दर 2.6% होती।

पहली तिमाही के जीडीपी अनुमानों की तुलना को जीडीपी श्रृंखला में किए गए बदलावों के संदर्भ में समझना जरूरी है। पहली तिमाही 2025-26 के अनुमानों में बदलाव का मतलब यह नहीं है कि मौजूदा वर्ष की वृद्धि को अधिक दिखाने के लिए अनुमान को कम किया गया है। यह जीडीपी श्रृंखला में समय-समय पर किए गए कार्यप्रणाली और आंकड़ों से जुड़े बदलावों को दर्शाता है।

बेंचमार्क-संकेतक पद्धति: तिमाही जीडीपी अनुमान बेंचमार्क-संकेतक पद्धति का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं। इस पद्धति में तिमाही अनुमानों में होने वाले बदलाव संबंधित उच्च-आवृत्ति संकेतकों में होने वाले बदलावों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

पिछले साल के बेंचमार्क में बदलाव से, अपने आप में, चालू वर्ष की वास्तविक आर्थिक गतिविधि या अनुमान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संकेतकों में कोई बनावटी बढ़ोतरी नहीं होती है।

तिमाही श्रृंखला में मात्रा या मूल्य से जुड़े सैकड़ों संकेतकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, मात्रा-आधारित संकेतकों में फसल उत्पादन में वृद्धि, सीमेंट उत्पादन सूचकांक में वृद्धि, तैयार इस्पात की खपत में वृद्धि और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में वृद्धि आदि शामिल हैं।



- **29 अगस्त 2025:** उस समय लागू 2011-12 आधार वर्ष वाली जीडीपी श्रृंखला के तहत, मौजूदा कीमतों पर पहली तिमाही 2025-26 की जीडीपी का अनुमान **86.05 लाख करोड़ रुपये** लगाया गया था।
- **फ़रवरी 2026:** 2022-23 आधार वर्ष वाली जीडीपी श्रृंखला शुरू होने के साथ, अनुमान को संशोधित करके **80.32 लाख करोड़ रुपये** कर दिया गया। इसमें अद्यतन आंकड़ा स्रोतों, बेहतर कार्यप्रणाली, संशोधित कवरेज और अन्य आवश्यक जानकारियों को शामिल किया गया।
- **5 जून 2026:** 2025-26 के लिए अनंतिम अनुमान जारी होने के साथ, पहली तिमाही 2025-26 के अनुमान को अपडेट करके **80.44 लाख करोड़ रुपये** कर दिया गया। यह बदलाव उपलब्ध संकेतकों और आंकड़ों में हुए अपडेट को दर्शाता है।
- **इसके बाद:** औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और उत्पादक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला को शामिल करने से आंकड़ों में और संशोधन हुआ, जिससे चालू कीमतों पर पहली तिमाही 2025-26 की जीडीपी **80.00 लाख करोड़ रुपये** हो गई।

इस अंतर को मौजूदा वर्ष की वृद्धि दर को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए पिछले वर्ष की जीडीपी में जानबूझकर की गई कटौती के रूप में देखना गलत है।

86.05 लाख करोड़ रुपये से घटकर 80.00 लाख करोड़ रुपये होना जीडीपी श्रृंखला में समय-समय पर किए गए संशोधनों का परिणाम है। ये संशोधन आधार वर्ष में बदलाव, बेहतर आंकड़ा स्रोतों और कार्यप्रणाली को शामिल करने तथा उपलब्ध संकेतकों को अद्यतन करने के कारण किए गए हैं।

सबसे जरूरी बात यह है कि पुरानी 2011-12 आधार वर्ष वाली श्रृंखला के 86.05 लाख करोड़ रुपये के अनुमान की तुलना सीधे नई 2022-23 आधार वर्ष वाली श्रृंखला के तहत मौजूदा पहली तिमाही 2026-27 के अनुमान से नहीं की जा सकती। इसके बजाय, वृद्धि दर की गणना एक ही और नवीनतम तुलना-योग्य जीडीपी श्रृंखला, यानी 2022-23 आधार वर्ष वाली श्रृंखला के अनुमानों के आधार पर की जाती है।

इसलिए, 2026-27 की पहली तिमाही के ₹88.27 लाख करोड़ के आंकड़े की तुलना 2025-26 की पहली तिमाही के 80.32 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से की जानी चाहिए थी, न कि पुरानी श्रृंखला के 86.05 लाख करोड़ रुपये के अनुमान से।

2. चूंकि 2026-27 की पहली तिमाही में मौजूदा और स्थिर कीमतों पर जीडीपी अनुमानों में काफी अंतर है, तो क्या इसका मतलब यह है कि इन अंतरों को ठीक करने पर अगले संशोधन दौर में जीडीपी अनुमानों में काफी बदलाव होगा?

पहली तिमाही 2026-27 के अनुमान मौजूदा उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं और जैसे-जैसे अधिक विस्तृत एवं अद्यतन स्रोत आंकड़े उपलब्ध होंगे, इनमें बदलाव हो सकता है। अतिरिक्त जानकारी शामिल होने के साथ विभिन्न पद्धतियों

के तहत अनुमान भी बदल सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप सांख्यिकीय विसंगति में भी बदलाव हो सकता है।

यह अंतर एक सांख्यिकीय संतुलन मद है, जो उत्पादन और व्यय पद्धतियों से तैयार किए गए जीडीपी अनुमानों के बीच अंतर के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए, केवल इसमें हुए बदलाव को इस बात का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए कि बताई गई जीडीपी कम या अधिक आंकी गई है।

इसलिए, हालांकि मौजूदा अंतर बाद के संशोधन दौर में बदल सकता है, लेकिन पहले से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि जीडीपी में निश्चित रूप से वृद्धि होगी या उसमें किसी विशेष मात्रा में बदलाव किया जाएगा।

किसी भी बदलाव की दिशा और उसकी मात्रा केवल अंतर को यांत्रिक रूप से समायोजित करने पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि उत्पादन एवं व्यय से जुड़े शुरुआती अनुमानों में होने वाले बदलावों पर निर्भर करेगी।

वर्तमान कीमतों पर अंतिम अनुमान जारी होने के समय यह अंतर बहुत कम या शून्य हो सकता है, जैसा कि वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के मामलों में देखा गया था।

पीके/केसी/एनके